आकाशवाणी केन्द्र शिमला

28.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18.00 बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभिन्न 66 परियोजनाओं को एफ.सी.ए क्लीयरेंस प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र से 77 सैद्धांतिक स्वीकृतियां भी सुनिश्चित की हैं जिनमें शोंगटोंग, थाना पलाऊं विद्युत परियोजना, शैक्षणिक संस्थान, हेलीपोर्ट, पेयजल आपूर्ति और सड़क अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एफ.सी.ए और एफ.आर.ए मामलों की निगरानी के लिए उपायुक्तों, मंडलीय वन अधिकरियों और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 70 फीसदी वन क्षेत्र है और जनहित परियोजनाओं के लिए वन भूमि बेहद अनिवार्य है। इसलिए इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त करना राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

वेतन

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सितम्बर माह का वेतन एक अक्तूबर और पेंशन का भुगतान 9 अक्तूबर को किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग द्वारा सरकारी कोषागार में होने वाले 'नकदी के प्रवाह' की समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले माह प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन 5 सिंतबर व पेंशनरों को 10 सितम्बर को पेंशन का भुगतान किया गया था।

जेल भरो आंदोलन

राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के विरोध में जगह–जगह पर धरने प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिमला सहित प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन किए गए। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिन्दू संगठनों ने केन्द्र सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने और

हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों व मजारों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसे लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। देवभूमि संघर्ष समिति ने गत दिनों वाम दलों के शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी बैनर तले आयोजित किए गए शांति व सद्भावना मार्च पर देवभूमि संघर्ष समिति ने सवाल उठाए। गौरतलब है कि शिमला नगर निगम की रेवेन्यू कोर्ट में मस्जिद की अवैध मंजिलों को लेकर सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होनी है ऐसे में हिन्दू संगठनों ने सीधी चेतावनी दी है की यदि उस दिन मस्जिद गिराने का फैसला नही हुआ तो जेल भरो आन्दोलन शुरु होगा।

राजेश धर्माणी

राज्य सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से बाजार मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दे रही है। ये बात नगर एवं ग्राम नियोजन व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मंडी के विजय मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़सू में 19वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि अध्यापक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्माणी ने कहा कि तकनीकी महाविद्यालयों में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन टैक्नोलॉजी सहित अन्य आधुनिक व भविष्योन्नमुखी कोर्स आरंभ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ए.आई का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में हमें अपना स्थान बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक स्किल मैनपावर तैयार करनी होगी ताकि अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन. ए.आई.आर. मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा।

चयन परीक्षा

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 के लिये आवेदन की तिथि 7 अक्टूबर तक

बढ़ा दी है। इस परीक्षा के माध्यम से सत्र 2025–26 के लिये कक्षा छः में प्रवेश लिया जायेगा। इच्छुक छात्र और उनके अभिभावक नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

नमस्कार